भारत – म्यांमार संबंध

भारत और म्यांमार के बीच 1600 किमी से अधिक लंबी भूमि सीमा तथा बंगाल की खाड़ी में एक समुद्री सीमा है। चार उत्तर पूर्वी राज्यों अर्थात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार के साथ लगती है। धर्म, भाषा एवं नृजाति की दृष्टि से दोनों देशों की विरासत साझी है। म्यांमार में भारतीय मूल के व्यक्तियों की आबादी अच्छी खासी है (अनुमानित तौर पर 1.5 - 2 मिलियन)। इसके अलावा म्यांमार दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा आसियान के लिए हमारा गेटवे है, जिसके साथ हम पूरब में देखो नीति तथा पूरब में काम करो नीति के माध्यम से अधिक आर्थिक एकीकरण का प्रयास कर रहे हैं। म्यांमार हमें उत्तर पूर्व के लिए एक वैकल्पिक पहुंच मार्ग की भी पेशकश करता है। दलहनों की आपूर्ति के अलावा म्यांमार में अपतटीय ब्लाकों से ऊर्जा आपूर्ति की संभावनाएं तथा कारोबारी अवसर जो अर्थव्यवस्था के खुलने से उत्पन्न हो रहे हैं, द्विपक्षीय संबंधों की नींव हैं।

म्यांमार के साथ संबंधों को सुदृढ़ करने की भारत की नीति है। 8 नवंबर 2015 के चुनावों में राष्ट्रीय लोकतंत्र लीग (एन एल डी) की हाल की विजय, जिसमें एन एल डी ने 323 सीटों में से 255 सीटें जीती हैं (निचले सदन में) और उच्च सदन की 168 में से 135 सीटें जीती हैं तथा क्षेत्रीय, राज्य संसद की 630 सीटों में से 475 सीटें जीती हैं, से भागीदारी को और सुदृढ़ करने के अवसर प्राप्त हुए हैं। विभिन्न संस्थानिक तंत्रों ने बढ़ते तथा बहुआयामी द्विपक्षीय संबंधों को गति प्रदान की है। भारत और म्यांमार के विदेश मंत्रियों की सह अध्यक्षता में भारत - म्यांमार संयुक्त परामर्श आयोग (जे सी सी) की पहली बैठक 16 जुलाई 2015 को नई दिल्ली में हुई थी। दोनों देशों के विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के बीच वार्ता को सुगम बनाने के लिए एक छत्रछाया तंत्र के रूप में संयुक्त परामर्श आयोग का गठन किया गया है। सचिव स्तर पर, इनमें विदेश सचिव / उप विदेश मंत्री के स्तर पर विदेश कार्यालय परामर्श (एफ ओ सी) (इसकी पिछली बैठक जुलाई 2014 में नई दिल्ली में और जुलाई 2013 में नाय पी ताव में हुई थी) तथा गृह सचिव / उप गृह मंत्री के स्तर पर राष्ट्र स्तरीय बैठक (एन एल एम) (19वीं एल एल एम का आयोजन 17 से 19 नवंबर 2014 के दौरान यंगून में और 18वीं एन एल एम का आयोजन 28 और 29 दिसंबर 2012 को नई दिल्ली में हुआ था) शामिल हैं। इनके अलावा तकनीकी स्तर तथा प्रचालन स्तर पर भी बैठकें होती हैं।

उच्च स्तरीय यात्राएं

उच्च स्तर पर अनेक दौरे किए गए हैं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी (1987), सीनियर जनरल थान शवे (2004 और 2010), राष्ट्रपति अब्दुल कलाम (2006), वाइस सीनियर जनरल मौंग अये (2008), उप राष्ट्रपति अंसारी (2009), राष्ट्रपति यू थेन सेन (अक्टूबर 2011 एवं दिसंबर 2012) तथा तत्कालीन प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह (मई 2012)। इन यात्राओं के दौरान महत्वपूर्ण करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं (सुरक्षा के गैर परंपरागत मुद्दों में सहयोग के लिए एम ओ यू, आसूचना सहयोग के लिए एम ओ यू, डी टी ए ए, बी आई पी पी ए, आपराधिक मामलों में एम एल ए टी) तथा अनेक विकास परियोजनाएं जैसे कि कलादन परियोजना, आनंद मंदिर का जीर्णोद्धार, अस्पताल उन्नयन, ओ एफ एल लिंक आदि पर काम चल रहा है। भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि आदि में अनेक अवसंरचना तथा सार्वजनिक हित की परियोजनाओं के लिए 297.43 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण तथा 477.63 मिलियन अमरीकी डालर का अनुदान प्रदान किया है।

प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 27 से 29 मार्च, 2012 के दौरान म्यांमार का राजकीय दौरा किया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह तथा राष्ट्रपति यू थेन सेन ने 12 करारों / एम ओ यू पर हस्ताक्षर किए जिसमें 500 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता शामिल है, जो हवाई सेवा, सीमा क्षेत्र विकास, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा के लिए उन्नत केन्द्र (ए सी ए आर ई) की स्थापना, राइस बायो पार्क म्यांमार की स्थापना तथा भारतीय सहायता से सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना, बार्डर हाट की स्थापना, संयुक्त व्यापार एवं निवेश फोरम, 2012-15 के लिए सी ई पी, दोनों देशों के थिंक टैंक / संस्थानों के बीच सहयोग के लिए एम ओ यू तथा 500 प्रशिक्षण स्लाटों के माध्यम से एच आर डी के लिए सहायता शामिल हैं। त्रिपक्षीय राजमार्ग तथा री - टिडिम सड़क जैसी नई सड़क परियोजनाओं के मद्देनजर म्यांमार के विकास के लिए भारत की प्रतिबद्धता का मूल्य 2 बिलियन अमरीकी डालर है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 12वीं आसियान – भारत शिखर बैठक तथा नौवीं पूर्वी एशिया शिखर बैठक में भाग लेने के लिए 11 से 13 नवंबर, 2014 के दौरान नाय पी ताव का दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति यू थेन सेन से मुलाकात की तथा डाव आंग सान सू की के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री जी ने म्यांमार में पी आई ओ / ओ सी आई समुदाय के लगभग 300 सदस्यों से भी बातचीत की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने 15 अक्टूबर 2015 को राष्ट्र व्यापी युद्ध विराम करार समारोह में भाग लिया जिसमें वह अन्यों के अलावा भारत के गवाह हस्ताक्षरकर्ता थे जिसमें चीन, थाईलैंड, यूरोपीय संघ, संयुक्त राष्ट्र और जापान का भी प्रतिनिधित्व था। भारत की मौजूदगी म्यांमार में चल रही शांति प्रक्रिया में भारत के समर्थन का प्रतीक थी।

विदेश मंत्री ने 14 से 16 दिसंबर 2012 के दौरान म्यांमार का आधिकारिक दौरा किया तथा म्यांमार के विदेश मंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की। भारत और म्यांमार के विदेश मंत्रियों ने म्यांमार के चिन राज्य में री-टिडिम सड़क के निर्माण के लिए एम यू पर हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्री तथा म्यांमार के उप राष्ट्रपति ने संयुक्त रूप से आई सी सी आर द्वारा आयोजित ''बौद्ध सांस्कृतिक विरासत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन'' और रंगून में सितागू अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अकादमी का उद्घाटन किया। विदेश मंत्री तथा म्यांमार के धार्मिक मामले मंत्री ने भारत के लोगों द्वारा म्यांमार को उपहार में प्रदान की गई सारनाथ शैली की बौद्ध प्रतिमा का संयुक्त रूप से अनावरण किया तथा शवे डैगन पगोडा के परिसर में ''बौद्ध सांस्कृतिक विरासत'' पर फोटो एवं पुस्तक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज ने चौथी पूर्वी एशिया शिखर बैठक की विदेश मंत्री बैठक तथा 21वीं आसियान क्षेत्रीय मंच की मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए 8 से 11 अगस्त, 2014 के दौरान नाय पी ताव का दौरा किया तथा 11 अगस्त, 2014 को एक आधिकारिक द्विपक्षीय दौरा किया।

रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने 21 और 22 जनवरी 2013 को म्यांमार का दौरा किया जिसमें रक्षा सचिव, नौसेना के वाइस चीफ, पूर्वी कमान के जी ओ सी इन सी तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। इस यात्रा के दौरान, रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति यू थेन सेन से मुलाकात की तथा कमांडर इन चीफ वाइस सीनियर जनरल मिन आंग हलेंग तथा रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल वाइ ल्विन से सहयोग पर बातचीत की।

लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार ने भारतीय संसदीय शिष्टमंडल के साथ 12 से 15 फरवरी, 2013 के दौरान म्यांमार का दौरा किया। इस यात्रा के दौरान लोक सभा अध्यक्ष ने राष्ट्रपति यू थेन सेन से मुलाकात की तथा पिथू हलउत्ता के स्पीकर थुरा यू शवे मान और अमयोथा हलउत्ता यू किन आंग मिंट के साथ चर्चा की। पिथू हलउत्ता के स्पीकर ने अतिथि लोक सभा अध्यक्ष के सम्मान में दावत दी तथा भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की।

नाय पी ताव में पूर्वी एशिया पर वैश्विक आर्थिक फोरम में भाग लेने के लिए वाणिज्य, उद्योग तथा कपड़ा मंत्री ने 6 से 8 जून 2013 के दौरान म्यांमार का दौरा किया। वाणिज्य मंत्री यू विन मिंट के साथ वाणिज्य, उद्योग एवं कपड़ा मंत्री ने यंगून में पहले भारत - म्यांमार संयुक्त व्यापार एवं निवेश मंच का उद्घाटन किया। सी आई एम श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 16 और 17 फरवरी 2015 को नाय पी ताव में यू विन मिंट के साथ संयुक्त व्यापार समिति (जे टी सी) की 5वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। इस यात्रा के दौरान सी आई एम ने यंगून में यू एम एफ सी सी आई में म्यांमार के उद्योगों के प्रमुखों के साथ बातचीत की तथा यंगून में भारतीय समुदाय द्वारा आयोजित एक सामुदायिक समारोह को संबोधित किया। अन्य यात्राओं में म्यांमार के सगैंग और मंडाले क्षेत्रों के मुख्य मंत्रियों की यात्राएं शामिल हैं जिन्होंने 110 सदस्यीय शिष्टमंडल के साथ नवंबर 2013 में संगाई महोत्सव में भाग लिया जिसमें कारोबारी, कलाकार, शिक्षाविद और मीडिया से जुड़े व्यक्ति शामिल थे। चेन्नई के निकट मल्लापुरम में 12 और 13 जनवरी 2016 को तीसरी सी एम एल वी (कंबोडिया, म्यांमार, लाओ पी डी आर, वियतनाम) व्यवसाय गोष्ठी का आयोजन किया गया। निवेश गंतव्य के रूप में म्यांमार इस गोष्ठी का मुख्य विषय था। वाणिज्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीमारमन तथा म्यांमार के उप वाणिज्य मंत्री डा. पर्विंट सैन ने अन्य सी एम एल वी देशों के मंत्रियों के साथ गोष्ठी की सह अध्यक्षता की। पिछले दशकों में भारतीय उद्योग के लिए निवेश गंतव्य के रूप में म्यांमार के संवर्धन के लिए प्रमुख गतिविधि होने के नाते इस गोष्ठी में दोनों देशों के अलावा अन्य सी एम एल वी देशों के शीर्ष कारोबारी नेताओं ने भाग लिया।

वाणिज्यिक संबंध

वाणिज्यिक सहयोग फोकस का एक अन्य क्षेत्र है। भारत और म्यांमार ने 1970 में एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। द्विपक्षीय व्यापार निरंतर बढ़ रहा है तथा यह 2014-15 में 1571.95 मिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया है (म्यांमार को निर्यात का मूल्य 773.74 मिलियन अमरीकी डालर तथा म्यांमार से आयात का मूल्य 1016.86 मिलियन अमरीकी डालर था) तथा भारत म्यांमार का चौथा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है, फिर भी व्यापार अपनी क्षमता से नीचे है। द्विपक्षीय व्यापार में कृषि क्षेत्र का दबदबा है। म्यांमार भारत को बींस और दलहनों तथा टिंबर एवं लकड़ी उत्पादों की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत की ओर से म्यांमार को जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है उनमें भेषज उत्पाद, इस्पात एवं लोहा के उत्पाद, विद्युत मशीनरी, खनिज तेल, रबर एवं रबर से बनी वस्तुएं, प्लास्टिक आदि शामिल हैं। मोरेह तथा जावखातर के माध्यम से बार्डर व्यापार 2013-14 में 51.68 मिलियन अमरीकी डालर पर पहुंच गया।

655 उद्यमों द्वारा 33 देशों से 45.237 बि लियन अमरीकी डालर के कुल अनुमानित निवेश में से 295.5 मिलियन अमरीकी डालर के अनुमोदित निवेश के साथ भारत 11वें सबसे बड़े निवेशक से ऊपर उठकर 10वें स्थान पर पहुंच गया है। भारत के अधिकांश निवेश तेल एवं गैस क्षेत्र में हैं। नए विदेशी निवेश कानून (2 नवंबर 2012) तथा संबंधित विभागों / मंत्रालयों द्वारा बनाए गए उप नियमों एवं कानूनों (31 जनवरी 2013) के बाद म्यांमार में निवेश में वृद्धि हो रही है। अब चुनिंदा क्षेत्रों में 100 प्रतिशत एफ डी आई की अनुमति है। भारतीय कंपनियों ने म्यांमार में निवेश करने में रुचि का प्रदर्शन किया है तथा जिन भारतीय कंपनियों द्वारा प्रमुख ठेके प्राप्त किए गए हैं उनमें जुबिलांट एनर्जी इंडिया - पी एस सी-1 आनशोर ब्लाक; पुंज लायड; जिंदल सा; वेलस्पून इंडिया; विहान नेटवर्क; निफा एक्सपोर्ट तथा ट्रोइका एक्सपोर्ट; एल एण्ड टी शामिल हैं। अधिक अनुकूल माहौल जिसमें अधिक हवाई, समुद्री एवं सड़क संपर्क के विकल्प शामिल हैं, से सहयोग को और प्रोत्साहन मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र में सहयोग निवेश एवं व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच व्यापारी लेनदेन को सुगम बनाने के उद्देश्य से यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया द्वारा म्यांमार के अनेक बैंकों (एफ एफ टी बी, एम आई सी बी, एम ई बी तथा 9 निजी बैंक) के साथ अनेक बैंकिंग करार किए गए हैं। यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया (यू बी आई) ने नवंबर 2012 में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोला है। यू बी आई के अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, एग्जिम बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक ने यंगून में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले हैं।

संयुक्त व्यापार समिति, दोहरा कराधान परिहार करार तथा द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार जैसे तंत्रों तथा व्यापार पर अन्य तकनीकी स्तरीय समिति ने व्यापार एवं निवेशों संबंधों को सुदृढ़ करने में बहुत योगदान दिया है। श्री सुनील मित्तल तथा यू आंग विन (अध्यक्ष, यू एम एफ सी सी आई, म्यांमार) की सह अध्यक्षता में 7 जून 2013 को यंगून में संयुक्त व्यापार एवं निवेश मंच (जे टी आई एफ) की पहली बैठक आयोजित की गई। म्यांमार हमारी ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने में एक महत्वपूर्ण साझेदार है। इसे स्वीकार करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय तथा म्यांमार के ऊर्जा मंत्रालय के बीच पेट्रोलियम क्षेत्र में सहयोग के लिए एक एम ओ यू पर हस्ताक्षर मार्च 2006 में राष्ट्रपति जी की म्यांमार यात्रा के दौरान किए गए।

विकास सहयोग तथा मानवीय राहत

विकास सहयोग हमारे संबंध का एक प्रमुख पहलू है तथा हमने अवसंरचना, क्षमता निर्माण, आपातकालीन राहत तथा अन्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए म्यांमार को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता की पेशकश की है। म्यांमार के लिए कुल विकास सहायता का मूल्य 2 बिलियन अमरीकी डालर के आसपास है।

आपदा राहत : 2008 में साइक्लोन नर्गिस, 2010 में शान राज्य में भूकंप तथा 2015 में साइक्लोन कोमेन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बाद मानवीय राहत के कार्यों में म्यांमार की मदद के लिए भारत ने शीघ्रता से और कारगर ढंग से कार्रवाई की है। हमने पुनर्वास कार्य, बायोमास गैसीफायर, सोलर टार्च तथा लालटेन के लिए तत्काल राहत सामग्री, चिकित्सा सहायता एवं रसद प्रदान की है। हमने 16 क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मरों को प्रतिस्थापित भी किया है तथा यंगून में शवे डैगन पगोडा परिसर की मरम्मत के लिए 2 लाख अमरीकी डालर का अनुदान दिया है। हमने शान राज्य के भूकंप प्रभावित क्षेत्र में राहत एवं पुनर्निर्माण कार्य के लिए 1 मिलियन अमरीकी डालर की सहायता भी दी है जिसमें से 250000 रुपए की राशि नकद अनुदान के रूप में दी

गई तथा शेष राशि का प्रयोग एक हाई स्कूल तथा 6 प्राथमिक विद्यालयों के पुनर्निर्माण के वित्त पोषण के लिए दिया गया। हमने राखिने राज्य के पुनर्वास के लिए म्यांमार सरकार को 200000 अमरीकी डालर की नकद राशि भी दान में दी है। भारत ने राखिन राज्य में समुदायों के बीच सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए म्यांमार सरकार को पुन: 1 मिलियन अमरीकी डालर की राशि प्रदान की जिसे म्यांमार सरकार ने 10 स्कूलों के निर्माण के लिए प्रयुक्त करने का निर्णय लिया है जो दोनों समुदायों के काम आएंगे तथा सामुदायिक सौहार्द बढ़ेगा। 10 स्कूलों के निर्माण का कार्य अब पूरा हो गया है तथा नए भवन से कक्षाएं शुरू हो गई हैं। साइक्लोन कोमेन से प्रभावित होने के शीघ्र बाद कलाय और मंडाले के लिए एयरफोर्स की 4 उड़ानों के माध्यम से खाद्य, दवा एवं राहत सामग्रियों की हमारी आपातकालीन आपूर्ति की बड़े पैमाने पर सराहना की गई है।

सांस्कृतिक संबंध

भारत और म्यांमार के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध हैं। भगवान बुद्ध के जीवन के भारत से जुड़ाव को देखते हुए विशेष रूप से बौद्ध समुदाय में बंधुत्व की गहरी भावना मौजूद है। हम कुछ प्रमुख पहलों के माध्यम से इस साझी विरासत का सर्वाधिक लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं : भारत सरकार बगान स्थित आनंद मंदिर के जीर्णोद्धार का काम कर रही है; भारत सरकार ने सारनाथ शैली की बुद्ध प्रतिमा की 16 फीट की एक प्रतिकृति दान में दी है जिसे यंगून में शवे डैगन पगोडा के परिसरों में लगाया गया है; आई सी सी आर तथा सितागू अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध अकादमी एवं म्यांमार के धार्मिक मामले मंत्रालय के समन्वय में विदेश मंत्रालय ने 15 से 17 दिसंबर 2012 के दौरान बौद्ध सांस्कृतिक विरासत पर एक अंतर्राट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इसके अलावा नियमित आधार पर भारत और म्यांमार की सांस्कृतिक मंडलियों द्वारा परफार्मेंस का आयोजन किया गया है। म्यांमार की मंडलियों एवं कलाकारों ने भारत में दक्षिण एशिया तथा आसियान सांस्कृतिक कार्यक्रमों में नियमित रूप से भाग लिया है।

संपर्क को द्विपक्षीय वाणिज्यिक, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा अन्य आदान प्रदान को प्रोत्साहित करने की कुंजी के रूप में देखा जा रहा है। भारत विकास की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं संचालित कर रहा है जिससे संपर्क में वृद्धि होगी जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं : कलादन परियोजना, री - टिडिम सड़ का निर्माण / उन्नयन, जिसके लिए एम ओ यू पर हस्ताक्षर दिसंबर 2012 में विदेश मंत्री की म्यांमार यात्रा के दौरान किए गए थे। हम टामू - कलामयो - कलेवा (टी के के) मैत्री सड़क पर 69 पुलों का निर्माण करने तथा म्यांमार होते हुए थाईलैंड में माई साट तक भारत में मोरेह से अचूक त्रिपक्षीय राजमार्ग स्थापित करने के लिए कलेवा - यार्गई सड़क के 126 किलोमीटर खंड का निर्माण करने के कार्य को हाथ में लेने के लिए म्यांमार के अनुरोध से सहमत हुए हैं। हम हवाई, रेल तथा समुद्री संपर्कों को मजबूत करने पर भी काम कर रहे हैं। मई 2012 में प्रधानमंत्री की म्यांमार यात्रा के दौरान हवाई सेवा करार पर हस्ताक्षर किए गए थे तथा दोनों देशों के बीच सीमा पारीय रेल लिंक एवं सीधे जहाजरानी लिंक की तकनीकी एवं वाणिज्यिक संभाव्यता का निर्धारण करने के लिए संयुक्त कार्य समूहों का गठन करने पर सहमति हुई थी। द्विपक्षीय हवाई सेवा करार भारत और म्यांमार दोनों देशों के कैरियर को तीसरा, चौथा और पांचवा फ्रीडम अधिकार प्रदान करता है। सीधी इम्फाल - मंडाले बस सेवा स्थापित करने तथा इस सेवा के प्रचालन के लिए विस्तृत रूपरेखा के लिए एक एम ओ यू पर वार्ता हुई है तथा उस पर आद्याक्षर किए गए हैं तथा अंतिम औपचारिक हस्ताक्षर की प्रतीक्षा है। एयर इंडिया ने 2014 के पीक सीजन के दौरान सप्ताह में एक बार दिल्ली - गया - यंगून के बीच एक सीधी उड़ान शुरू की है। शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2014 मे भारत और म्यांमार के बीच एक सीधा समुद्री लिंक शुरू किया है।

उपयोगी संसाधन :

भारतीय दूतावास, यंगून की वेबसाइट :
www.indiaembassyyangon.net/index.php?lang=en
भारतीय दूतावास, यंगून का फेसबुक पृष्ठ :
www.facebook.com/IndiaInMyanmar?reg=ts&fref=ts
भारतीय दूतावास, यंगून का ट्विटर पृष्ठ :
twitter.com/IndiaInMyanmar
भारतीय दूतावास, यंगून का फ्लिकर पृष्ठ :
www.flickr.com/photos/129492273@N03/

इंडिया ग्लोबल : एआरआई एफ एम गोल्ड जो भारत तथा म्यांमार संबंधों पर आधारित कार्यक्रम है : www.youtube.com/watch?v=Any_IdE55gA

***

फरवरी, 2016